RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 341
दि. 14.04.2026, मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' को संबोधित किया

भारत की नारी शक्ति ने असीम योगदान दिया है: प्रधानमंत्री

हमारे देश में पंचायती राज संस्थाएं महिला नेतृत्व का उल्लेखनीय उदाहरण हैं: प्रधानमंत्री

सरकार जीवन के हर स्तर पर महिलाओं की सहायता कर रही है : प्रधानमंत्री

आज महिलाएं उन सेक्टरों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं जिन्हें कभी पुरुष प्रधान माना जाता था : प्रधानमंत्री

भारत की नारी शक्ति ने अपनी कड़ी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास के बल पर नई ऊंचाइयों को छुआ है; अब हमें मिलकर अवसरों का विस्तार करके उन्हें और सशक्त बनाना होगा: प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बैसाखी के शुभ अवसर पर और देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष समारोह से पूर्व संबोधित करते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। श्री मोदी ने कहा, "भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक लेने जा रहा है, एक ऐसा निर्णय जो नारी शक्ति को समर्पित है।"

प्रधानमंत्री ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश की संसद एक नया इतिहास रचने के निकट है जो अतीत के विजन और भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। सामाजिक न्याय के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि देश एक समतावादी भारत की कल्पना करता है जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा नहीं बल्कि कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री ने कहा, "राज्य विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक, दशकों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है।"

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 में नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने का स्मरण करते हुए कहा कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था और सभी दलों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि इसे हर हाल में 2029 तक क्रियान्वित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समय पर लागू किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं की भागीदारी से हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ हो। इसके लिए संसद के बजट सत्र का विशेष सत्र 16 अप्रैल से आरंभ होगा। श्री मोदी ने कहा, "हमारा प्रयास और प्राथमिकता यह है कि यह कार्य संवाद, सहयोग और भागीदारी के माध्यम से पूरा किया जाए, जिससे संसद की गरिमा बढ़ेगी।"

इस मुद्दे पर महिलाओं के बीच व्याप्त राष्ट्रव्यापी उत्साह की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर की महिलाएं विधानसभाओं और लोकसभा तक पहुंचने की अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त कर रही हैं। उनके सपनों को नई उड़ान मिली है और देश में सकारात्मक माहौल का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ने सभी महिलाओं से इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बनाए रखने और अपने सांसदों से मिलकर अपने विचार और अपेक्षाएं साझा करने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान सभा तक महिलाओं के योगदान का उल्लेख करते हुए स्वतंत्र भारत की नींव रखने में नारी शक्ति की असीम भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रतिनिधित्व के अवसर प्राप्त करने वाली महिलाओं ने राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर वित्त मंत्री तक, महिलाएं इतने महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। श्री मोदी ने कहा, "राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, जहां भी महिलाएं रही हैं, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।"

प्रधानमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को महिला नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि आज स्थानीय सरकारी निकायों में 14 लाख से अधिक महिलाएं सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। लगभग 21 राज्यों में पंचायतों में उनकी भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, "राजनीति और सामाजिक जीवन में लाखों महिलाओं की यह सक्रिय भागीदारी विश्व के अग्रणी नेताओं और राजनीतिक विशेषज्ञों को भी आश्चर्यचकित करती है और भारत के गौरव को बढ़ाती है।"

प्रधानमंत्री ने विभिन्न अध्ययनों को संदर्भित करते हुए कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से व्यवस्थाओं में संवेदनशीलता आई है। इससे जल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मुद्दों पर अधिक समर्पित कार्य करने को प्रोत्साहन मिला है। श्री मोदी ने कहा, "जल जीवन मिशन की सफलता इसका एक उदाहरण है, जहां पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि स्थानीय निकायों और संस्थानों में वर्षों से कार्यरत लाखों महिलाओं के पास व्यापक अनुभव है और वे बड़ी भूमिकाओं के लिए तैयार और उत्सुक हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन इन सभी महिलाओं के जीवन में एक बड़ा अवसर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, "पंचायत से संसद तक की यात्रा सुगम होने वाली है।"

विकसित भारत की यात्रा में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि उनकी सरकार ने 2014 से महिलाओं के जीवन चक्र के हर चरण के लिए योजनाएं बनाई हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बहनों और बेटियों की सेवा के लिए तत्पर है। श्री मोदी ने कहा, "हमने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, मातृ वंदन योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की और बेटियों की शिक्षा में सहायता देने के लिए उच्च ब्याज वाली सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की।"

व्यापक सहायता प्रणाली का विस्तृत विवरण देते हुए प्रधानमंत्री ने समय पर टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय, लगभग निशुल्क सैनिटरी नैपकिन, खेल इंडिया योजना के तहत वित्तीय सहायता और सैनिक विद्यालयों एवं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के द्वार खोलने का उल्लेख किया। लोगों के जीवन के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गैस कनेक्शन प्रदान किए, हर घर नल से जल अभियान ने घरों तक पानी पहुंचाया, निशुल्क राशन योजना ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और आयुष्मान योजना ने 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "जन औषधि केंद्रों द्वारा दवाओं पर 80 प्रतिशत तक की छूट सहित इन सभी पहलों से मुख्य रूप से हमारी बहनों और बेटियों को लाभ हुआ है।"

महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर निर्णय और योजना में इस पहलू को प्राथमिकता दी गई है। पहले पारिवारिक संपत्ति मुख्य रूप से पुरुषों के नाम पर पंजीकृत होती थी, लेकिन पीएम आवास योजना के तहत घरों को प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया गया है। श्री मोदी ने कहा, "पिछले 11 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस निर्णय से लाभ हुआ है और वे अपने घरों की स्वामी बन गई हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं।"

प्रधानमंत्री ने वित्तीय समावेशन का उल्लेख करते हुए याद दिलाया कि 2014 में करोड़ों महिलाओं ने कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था। जन धन योजना ने 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए बैंक खाते खोले। प्रधानमंत्री ने कहा, "आज हमारी बेटियां नए व्यवसायों में अपनी पहचान बना रही हैं और मुद्रा योजना के तहत लिए गए ऋणों में से 60 प्रतिशत से अधिक महिलाओं द्वारा लिए गए हैं।"

प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप क्रांति में महिलाओं के नेतृत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पंजीकृत स्टार्टअप्स में से 45 प्रतिशत से अधिक में कम से कम एक महिला निदेशक के रूप में कार्यरत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि करियर प्रभावित न हों, मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। ॰

प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे

इस गलियारे से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय 6 घंटे से घटकर लगभग 2.5 घंटे रह जाएगा

गलियारे को कई विशेषताओं के साथ डिजाइन किया गया है जिनका उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष में अत्यधिक कमी लाना है

इस परियोजना में 12 किलोमीटर लंबा वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है, जो एशिया के सबसे लंबे गलियारों में से एक है

प्रधानमंत्री वन्यजीव गलियारे का दौरा और समीक्षा भी करेंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11 :15 बजे उत्तर प्रदेश के

सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे के ऊंचे खंड पर बने वन्यजीव गलियारे की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11:40 बजे देहरादून के पास स्थित जय मां दात काली मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद, प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 12:30 बजे देहरादून में एक सार्वजनिक समारोह में दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।

213 किलोमीटर लंबा, छह लेन वाला और एक्सेस कंट्रोल्ड दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। यह गलियारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से होकर गुजरता है और दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय वर्तमान में छह घंटे से अधिक से घटकर लगभग ढाई घंटे हो जाएगा।

इस परियोजना के कार्यान्वयन में निर्बाध उच्च गति कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 10 इंटरचेंज, तीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी), चार प्रमुख पुल और सड़क किनारे 12 जन सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश

राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने डॉ. बी.आर. आंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है, 'भारतीय संविधान के प्रमुख निमार्ता और महान समाज सुधारक, बाबासाहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर, मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ।

बाबासाहब आंबेडकर एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, प्रखर चिंतक, न्यायविद और समतामूलक सामाज व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपना जीवन समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया ।

सीएम योगी करेंगे बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित, सभी जनपदों में जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचकर उनके अधिकारों, संविधान और समानता के मूल्यों की जानकारी देंगे

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष आंबेडकर जयंती को अभूतपूर्व स्तर पर मनाने की तैयारी की गई है। योगी सरकार ने इसे केवल एक स्मृति दिवस न रखकर सामाजिक न्याय, जागरूकता और जनसंपर्क के व्यापक अभियान के रूप में परिवर्तित कर दिया है।

प्रदेश के सभी जनपदों और विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें जनप्रतिनिधि सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनके अधिकारों, संविधान और समानता के मूल्यों की जानकारी देंगे।

हजरतगंज स्थित आंबेडकर महासभा परिसर में होने वाला मुख्य कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरूआत बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बाबा साहब के अस्थिकलश पर पुष्पांजलि और बुद्ध वंदना के साथ होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

योगी सरकार की मंशा है कि बाबा साहब के विचार- समानता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जाए। इसी दिशा में यूपी के प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करेंगे। इससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी और लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूती मिलेगी।

बाबा साहब की प्रतिमाओं पर लगाए जाएंगे छत्र

योगी सरकार ने आंबेडकर जयंती से पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमाओं पर छत्र लगाए जाएंगे, साथ ही बाउंड्री वॉल और सौंदर्यीकरण का कार्य भी कराया जाएगा। इस निर्णय को ऐतिहासिक कदम बताते हुए डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि इससे दलित समाज और आंबेडकर अनुयायियों में खासा उत्साह है।

14 अप्रैल को प्रदेश नजर आयेगा आंबेडकरमय

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं में भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें विचार गोष्ठियां, भाषण, निबंध प्रतियोगिताएं और वाद-विवाद शामिल हैं, जिनके माध्यम से नई पीढ़ी को बाबा साहब के योगदान और उनके संघर्षों से परिचित कराया जाएगा।

योगी सरकार की यह पहल स्पष्ट करती है कि वह सामाजिक समरसता और जनभागीदारी को प्राथमिकता दे रही है। 14 अप्रैल को पूरा प्रदेश 'आंबेडकरमय' नजर आएगा।

बाबा साहब के योगदान पर होगी विशेष चर्चा

वहीं समाज कल्याण विभाग के सभी कार्यालयों, विद्यालयों, छात्रावासों और संस्थाओं में भी आयोजन होंगे। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में भी विशेष कार्यक्रम होंगे। इनमें बाबा साहब डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा एवं चित्र पर माल्यार्पण, विचार गोष्ठियां, निबंध, भाषण और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उनके जीवन, शिक्षाओं और संविधान निर्माण में योगदान पर विशेष चर्चा होगी।

मूर्ति विकास योजना को मिल चुकी है मंजूरी

सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट डॉ. बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना को मंजूरी दे चुकी है, जिसके तहत प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक न्याय के महानायकों के 10-10 स्मारकों और प्रतिमाओं का विकास एवं सौंदर्यीकरण कराया जाएगा।

'भारत, रूस और चीन की भूमिका अहम', अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान का बड़ा बयान

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। मुंबई में ईरान के महावाणिज्यदूत सईद रजा मोसयेब मोतलाघ ने बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय स्थिरता स्थापित करने में प्रमुख वैश्विक शक्तियों, विशेषकर भारत की रचनात्मक भूमिका की सराहना की है।

नई दिल्ली की कूटनीति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए मोतलाघ ने कहा कि भारत ने चीन और रूस के साथ मिलकर सैन्य हस्तक्षेप की बजाय वैश्विक शांति की बहाली को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी युद्धोन्माद को रोकने में भारत, रूस और चीन की भूमिका अहम होगी।

'न हमले को उचित माना और न समर्थन किया'

मोतलाघ ने बताया, "भारत, चीन और रूस ने अपने हितों को जोखिम में डालकर भी संघर्ष में हस्तक्षेप न करके यह प्रदर्शित किया है कि वे शांति चाहते हैं। उन्होंने अमेरिकी हमले को उचित नहीं माना और न ही उसका समर्थन किया, न ही उन्होंने ईरान को सैन्य सहायता देने की स्थिति में खुद को रखा। बल्कि, उन्होंने शांति को बढ़ावा देने और आर्थिक बाजारों को स्थिर करने का प्रयास किया।"

'वैश्विक हितधारकों के रूप में काम किया'

महावाणिज्यदूत ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि इन शक्तियों ने जिम्मेदार वैश्विक हितधारकों के रूप में कार्य किया है, फिर भी वॉशिंगटन की ओर से पारस्परिक सहयोग की कमी के कारण तनाव कम करने का मार्ग अवरुद्ध है।

उन्होंने कहा, "हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक वे अमेरिका को समझाने में सफल नहीं हुए हैं। फिर भी, इन तीनों प्रमुख शक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अमेरिका को युद्धोन्माद बंद करने के लिए राजी करने और इजरायल की निरंकुश और दमनकारी सरकार पर दबाव डालने के लिए अपना प्रभाव डालें, जो विश्व में अनैतिक आचरण का स्त्रोत है।"

शांति वार्ता विफल होने के बाद पेजेश्कियन और पुतिन ने की फोन पर बात

पाकिस्तान में अमेरिका के साथ राजनयिक शांति वार्ता विफल होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रविवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की।

ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर एक बयान साझा किया। इसके मुताबिक, दोनों नेताओं ने बातचीत के दौरान क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे ताजा घटनाक्रमों की समीक्षा की, जिसमें क्षेत्र में चल रहे युद्धविराम की मौजूदा स्थिति भी शामिल थी।

पूरब में आंधी तो पश्चिम में बढ़ेगी तपिश, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा समेत वेस्ट यूपी के तमाम जिलों में पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है

(जीएनएस)।

लखनऊः कुछ दिनों के सुहावने मौसम के बाद उत्तर प्रदेश में अब हालात बदल रहे हैं। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है, वहीं पश्चिमी यूपी में सूरज की तपिश बरकरार रहेगी। गर्म हवाओं के चलते लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक हफ्ते तक आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और तगड़ी धूप पड़ेगा। नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा समेत वेस्ट यूपी के तमाम जिलों में पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। पिछले दो दिन के भीतर ही तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोत्तरी देखी जा चुकी है।

झांसी और प्रयागराज रहे सबसे गर्म

अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो झांसी और प्रयागराज में 12 अप्रैल को तापमान सबसे ज्यादा रहा। यहां पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लखनऊ में 36 डिग्री तो वाराणसी में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रेकॉर्ड किया गया।

6 से 8 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा

मौसम विभाग का कहना है कि 15 से 18 अप्रैल के बीच मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। इस महीने बारिश होने के आसार बहुत कम हैं। प्रदेश में अगल दो सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। बारिश के कोई आसान नहीं है। हवा का रुख बदलेगा। पूर्वी दिशा से आने वाली हवाओं से वातावरण में नमी घटेगी। गर्मी में और इजाफा होगा। रात और दिन के औसत तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोत्तरी हो सकती है।

13 से 17 अप्रैल तक मौसम का हाल जानिए

13 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। गर्मी बढ़ेगी और रात के वक्त भी उमस महसूस होगी। 14 अप्रैल को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में आसमान साफ रहेगा। तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज धूप से गर्मी बढ़ेगी। 15 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। बारिश या आंधी की चेतावनी नहीं है। 16 अप्रैल को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। हल्की की हवा सकती है। वहीं, 17 अप्रैल को पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहेगा। मौसम

प्रदेश में मौसम शुष्क होने के बाद पिछले चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में औसतन छह से आठ डिग्री सेल्सियस की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके बावजूद अधिकांश जिलों में तापमान अब भी सामान्य से नीचे बना हुआ है, लेकिन सोमवार से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का पारा चढ़ जाएगा। तापमान में प्रभावी वृद्धि होगी।

सम्पादकीय

पाकिस्तान में हुई शान्ति वार्ता का विफल होना एक नये संकट का शंखनाद

कुचलना होगा देश में पनपते आतंकवादी समूह को, देश के आन्तरिक हालातों को उत्तरदाई तंत्र में बैठे जिम्मेदार लोग किन्हीं खास कारणों से निरंतर अदृष्टिगत करते चले जा रहे हैं। उधार लेकर घी पीने वाले तंत्र के आन्तरिक हालात बद से बदतर हो चुके हैं मगर सत्ता हथियाने के लिए कभी लैपटाप बांटे जाते हैं तो कभी स्कूटी। वर्तमान परिस्थितियों से समूचा संसार जूझ रहा है। पाकिस्तान में हुई शान्ति वार्ता का विफल होना एक नये संकट का शंखनाद माना जा रहा है। ईरान संरक्षित हिजबुल्लाह, हूती, हमास जैसी दहशतगर्द जमातें खुलेआम मिसाइल, ड्रोन और राकेट लांचर सहित अत्याधुनिक हथियारों से हमले कर रहे हैं। आतंक परस्त देशों के कवच में कट्टरपंथी जमातें दहशतगर्दो की फौजें तैयार करने में जुटे हैं। अमन, चैन, भाईचारे को गजवा–ए–दुनिया निगलती जा रही है। कहीं यहूदियों को समाप्त करने की धमकियां दी जा रहीं हैं तो कहीं हिन्दुओं को। ईसाई और पारसियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यह हालात दुनिया के साथ–साथ देश के अन्दर भी बेलगाम होते जा रहे है। अतीत गवाह है कि ईश निंदा के मनगढन्त आरोप लगाकर सर तन से जुदा करने वाली प्रायोजित भीड़ एकत्रित की जाती है और फिर पूर्व नियोजित षडयंत्र को अमली जामा पहना दिया जाता है। राष्ट्रविरोधी ताकतें सीमापार से मिलने वाले धन से कट्टरता को पोषित कर रहीं हैं, भय का वातावरण निर्मित कर रहीं हैं और बना रहीं है आन्तरिक युद्ध के हालात। देश के लगभग प्रत्येक शहर, कस्बे और गांव में वैमनुष्यता का जहर फैल चुका है जिसे खास धर्मिक स्थानों से निरंतर संरक्षण दिया जा रहा है। हर जगह अवसरवादियों की जमातें मौके की तलाश में हैं। किसी भी मनगढ़न्त मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाकर देश भर में अशान्ति फैलाने के निरंतर प्रयास होते रहे हैं जिस पर उत्तरदायी तंत्र द्वारा हमेशा ही बेखबर होने का ढोंग रचा जाता रहा है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके मकान, दुकान, कारखाने लगाये जा रहे हैं। इन अवैध निर्माणों को सोची समझी योजना के तहत सकरी गलियों में बहुमंजिला इमारतें के साथ तैयार किया जाता है ताकि सुरक्षाबलों की आमद के दौरान आामण की व्यूह रचना का लाभ उठाया जा सके। देश की लगभग हर बसाहट में खास झंडा लगाकर अपनी उपस्थिति, कट्टरता और एकता का सबूत देने वाले जुल्म की नई इबारत लिखने में लगे हैं जिस पर कार्यपालिका जानबूझकर मौन धारण रखे हुए है। इन अवैध परिसरों में अवैध ढंग से विद्युत, जल और शासकीय सुविधाओं का खुलकर निःशुल्क उपयोग हो रहा है। ऐसे लगभग सभी स्थानों पर स्थानीय निकायों ने सुविधाओं का अम्बार भी लगा दिया है। जनप्रतिनिधियों ने वोट बैंक के लिए अनेक अवैध निर्माणों को वैध कराना भी शुरू कर दिया है। इन स्थानों को अभेद किले के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है जो आने वाले समय में आामण का केन्द्र बनेंगे। इन स्थानों पर भारी मात्रा में अवैध असलहे, गोलाबारूद और घातक संसाधन मौजूद होने की खबरें भी निरंतर आ रहीं हैं। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाली अनेक पाठशालाओं में जहरीली पौध तैयार की जा रही है। लगभग हर आबादी में ऐसे आतंकी संगठन मौजूद है जिन्हें खूनी खेल खेलने में महारत हासिल है। अनेक राजनैतिक दलों के कद्दावर नेताओं से लेकर लालफीताशाही की एक खास बिरादरी खुलकर उनके साथ खड़ी दिखती है। नियम, कानून और कायदे केवल निरीह, गरीब और लाचार तक ही सीमित होकर रह गये हैं या फिर जुल्मी को बचाने हेतु संविधान की धारायें प्रयुक्त होतीं हैं। भीड़ तंत्र के आगे कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह नतमस्तक हो चुकी है। वोट बैंक बढ़ाने की मानसिकता अब दावानल बनकर उभर चुकी है। आर्य है कि धरातल की वास्तविक स्थिति को नजरंदाज करते हुए चुनावी धरातल पर मुफ्तखोरी की निरंतर घोषणायें हो रहीं हैं। ऐसे राजनैतिक दलों को अपने घोषणा–पत्रों की पूर्ति हेतु पार्टी फंड से खर्च करना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि जनता पर टैक्स का दबाव बढ़ाकर हरामखोरों की फौज तैयार करके उन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों हेतु सुगम समय प्रदान करने वाले राजनैतिक दल ही सत्ता सुख की चाह में आत्मघाती कदम उठा रहे हैं।

दिल्ली में इलाज महंगा, लखनऊ में सस्ता, जानें कैसे आपकी लोकेशन तय करती है प्रीमियम

(जीएनएस)।

क्या आप जानते हैं कि लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट होते ही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 50% तक बढ़ सकता है? सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां आपके रहने की जगह के हिसाब से पैसे वसूलती हैं. आसान भाषा में कहें तो शहर बदलने के साथ केवल आपका पता और माहौल ही नहीं बदलता, बल्कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बदल जाता है.

शहर शिफ्टिंग से पहले समझें इंश्योरेंस के ये गणित.

नई दिल्ली. अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल, शहर बदलने का असर सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल या खर्चों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी इससे सीधे प्रभावित होती है. क्या आप जानते हैं कि लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट होते ही आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 50% तक बढ़ सकता है? सुनने में यह किसी छिपी हुई लागत जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बीमा कंपनियों का एक ठोस गणित काम करता है.

क्यों बदल जाते हैं प्रीमियम?

हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम तय करते समय आपके शहर को एक अहम फैक्टर मानती हैं. कंपनियां प्रीमियम तय करने के लिए 'जोन-बेस्ड प्राइसिंग' (ङ्मल्ली-इंरींढङ्मल्लॅ) का इस्तेमाल करती हैं. आसान भाषा में कहें तो, बीमा कंपनियां भारत के शहरों को उनके मेडिकल खर्चों के आधार पर अलग-अलग जोन में बांटती हैं.

जोन 1: इसमें दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जैसे महानगर आते हैं, जहां इलाज सबसे महंगा है.

जोन 2: इसमें लखनऊ, जयपुर, पुणे और कोलकाता जैसे शहर शामिल हैं.

जोन 3: इसमें छोटे शहर और ग्रामीण इलाके आते हैं.

बीमा कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम तय करने के लिए किस आधार पर शहरों को जोन में बांटती हैं?

अशिक्षा स्तर के आधार पर

इमेडिकल खर्चों के आधार पर

उमौसम के आधार पर

ऊजनसंख्या के आधार पर कंपनियां

उदाहरण के लिए अगर एक 25 साल आदमी दिल्ली (जोन 1) में रहता है, तो उसे एक बेसिक कवर के लिए लगभग 15,111 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. वहीं, वही आदमी अगर लखनऊ (जोन 2) में रहता है, तो उसका प्रीमियम गिरकर लगभग 10,012 रुपये हो जाएगा. यह अंतर इसलिए है क्योंकि दिल्ली के बड़े अस्पतालों में कमरे का किराया, डॉक्टर की फीस और सर्जरी का खर्च लखनऊ की तुलना में कहीं ज्यादा होता है.

अस्पताल एक, बिल अलग-अलग

पॉलिसीबाजार के एक्सपर्ट के अनुसार, एक ही ब्रांड के अस्पताल का बिल अलग-अलग शहरों में अलग हो सकता है. उदाहरण के तौर पर, मेदांता जैसे अस्पताल में 'अपेंडिक्स' का ऑपरेशन अगर किसी छोटे शहर में 80,000 रुपये से 1.2 लाख रुपये के बीच होता है, तो वही प्रक्रिया दिल्ली के अस्पताल में 2 लाख रुपये के पार जा सकती है.

सस्ती पॉलिसी का 'छिपा हुआ खतरा'

अक्सर लोग प्रीमियम के पैसे बचाने के चक्कर में छोटे शहर (लोअर जोन) के पते पर पॉलिसी ले लेते हैं. लेकिन यह बचत क्लेम के समय भारी पड़ सकती है. अगर आपके पास जोन-3 की पॉलिसी है और आप अचानक दिल्ली जैसे जोन 1 के अस्पताल में इलाज कराते हैं, तो कंपनियां 'को-पेमेंट' क्लॉज लागू कर देती हैं. इसका मतलब यह है कि अस्पताल के कुल बिल का एक निश्चित हिस्सा (जैसे 20% या 30%) आपको अपनी जेब से भरना होगा.

सही चुनाव कैसे करें?

इंश्योरेंस एक्सपर्ट की सलाह है कि पॉलिसी लेते समय केवल 'आज' का पता न देखें, बल्कि यह सोचें कि इमरजेंसी में आप कहां इलाज कराना चाहेंगे. अगर आप अक्सर सफर करते हैं या भविष्य में मेट्रो शहर जाने की संभावना है, तो 'पैन-इंडिया' बेस्ड प्रीमियम चुनें. अगर आप परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं, तो तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी दें. जानकारी छुपाने पर क्लेम खारिज भी हो सकता है.

राष्ट्रपति ने एम्स राजकोट के दीक्षांत समारोह को सम्बोधित किया

"समाज में गहरा बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं कुशल और सामाजिक रूप से जागरूक डॉक्टर ": राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

(जीएनएस)।

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज गुजरात के राजकोट में एम्स राजकोट के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर उसकी गरिमा बढ़ाई।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि किफायती लागत पर विश्व स्तरीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए देश भर में कई एम्स स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलकदमियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए अनुसंधानों और मरीजों की देखभाल के जरिये स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के प्रति एम्स की प्रतिबद्धता सराहनीय है।

राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स राजकोट एक नया संस्थान है। चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और सेवा के क्षेत्रों में इसे अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है। उन्होंने एम्स राजकोट के नीति निमार्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने उद्देश्यों में न केवल एम्स के मुख्य लक्ष्यों को शामिल करें, बल्कि इस क्षेत्र की विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान को भी प्राथमिकता दें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संगठन के स्वस्थ विकास में सुशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरूआत में ही उठाए गए कदमों का इस संस्थान के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा पेशा केवल एक व्यवसाय नहीं है; यह मानवता की सेवा के प्रति एक प्रतिबद्धता भी है। यह पेशा न केवल वैज्ञानिक ज्ञान की मांग करता है बल्कि इसमें संवेदनशीलता, धैर्य और विनम्रता की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो सफेद कोट पहनते हैं, वह बीमारी और अनिश्चितता के क्षणों में समाज द्वारा उन पर किए गए भरोसे का प्रतीक है जो मरीज बीमारी और अनिश्चितता के क्षणों में उन पर करता है। इस भरोसे को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी डॉक्टरों के कंधों पर है।

राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति अभूतपूर्व गति से हो रही है। आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, प्रिसिजन मेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ चिकित्सा जगत के स्वरूप और संभावनाओं को तेजी से बदल रही हैं। उन्होंने स्नातक हो रहे विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे इन बदलावों को अपनाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीकों को अपनाकर, वे न केवल अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा पाएँगे, बल्कि बीमारियों का अधिक प्रभावी ढंग से इलाज भी कर पाएँगे। हालाँकि, चिकित्सा में मानवीय संवेदना की भूमिका की जगह कोई और नहीं ले सकता। एक डॉक्टर के कोमल शब्द, आश्वस्त करने वाली मुस्कान और मरीज को सुनने का धैर्य, बीमारी को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं, जो सिर्फ दवाएँ नहीं कर सकतीं।

राष्ट्रपति ने कहा कि एक अच्छा डॉक्टर होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालाँकि, ईमानदारी, करुणा और परोपकार की भावना जैसे मानवीय मूल्यों से ओत-प्रोत डॉक्टर होना इससे भी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कुशल और सामाजिक रूप से जागरूक डॉक्टरों में समाज में गहरा बदलाव लाने की शक्ति होती है। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी स्थिति का रचनात्मक उपयोग करके राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।

राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये प्रयास पहले से ही सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। हालांकि, इन पहलों को और अधिक गति तब मिलेगी जब सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस संदर्भ में, एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हें चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करके देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को दिशा दिखाने का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एम्स राजकोट, सभी के लिए समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर नए मानक स्थापित करेगा।

सरकार ने स्टार्टअप के लिए पूंजी जुटाने हेतु ₹10,000 करोड़ की राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की अधिसूचना जारी की

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0; गहन प्रौद्योगिकी, प्रारंभिक विकास चरण और नवाचार आधारित विनिर्माण स्टार्टअप का समर्थन करेगा

(जीएनएस)।

सरकार ने कुल ₹10,000 करोड़ की राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0) की अधिसूचना जारी की है, जिसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए उद्यम और विकास पूंजी जुटाना है।

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0; स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस 1.0) के मजबूत प्रदर्शन पर आधारित है, जो 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के तहत शुरू किया गया था ताकि वित्तपोषण की कमी को पूरा किया जा सके और स्टार्टअप्स के लिए घरेलू पूंजी को उत्प्रेरित किया जा सके।

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 के पास 16वीं और 17वीं वित्त आयोग की अवधि के दौरान पात्र वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की प्रतिबद्धताओं के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि होगी।

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 के तहत निवेश उन वैकल्पिक निवेश कोष पर केंद्रित होंगे जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का समर्थन करते हैं, जिनमें गहन प्रौद्योगिकी (डीप टेक) स्टार्टअप्स, छोटे एआईएफ द्वारा समर्थित प्रारंभिक विकास चरण के स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी-संचालित और नवाचार आधारित निर्माण स्टार्टअप्स तथा क्षेत्र या चरण से स्वतंत्र स्टार्टअप शामिल हैं।

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 एआईएफ के लिए एक संरचित चयन प्रक्रिया का पालन करेगा, जिसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुभवी लोगों से बने उद्यम पूंजी निवेश समिति (वीसीआईसी) द्वारा स्क्रीनिंग शामिल होगी। इस योजना में मजबूत निगरानी और निरीक्षण तंत्र शामिल हैं तथा योजना के कार्यान्वयन और प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) भी गठित की जाएगी। इसमें एक व्यापक रूपरेखा के तहत उचित शासन सुरक्षा के साथ सरकार और संस्थागत निवेशकों द्वारा सह-निवेश के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) वीसीआई की संरचना और संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी करेगा।

उम्मीद है कि स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0, भारत के नवाचार-प्रेरित विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उन स्टार्टअप्स का समर्थन करेगा, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियां, उत्पाद, और समाधान तैयार करते हैं। यह योजना भारत की आर्थिक दृढ़ता को मजबूत करने, विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने, उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन करने और भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में योगदान देगी।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अधिसूचना की तारीख से योजना के कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के रूप में योजना के संचालन की शुरूआत करेगा । इसके अलावा, प्रस्तावित योजना को लागू करने के लिए एक अन्य घरेलू कार्यान्वयन एजेंसी का भी चयन किया जाएगा।

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0, केंद्रीय सरकार द्वारा 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं में निवेश करने के लिए सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) की निधि में योगदान देगा।

विकसित भारत @ 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप, यह कोष उद्यमियों को सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की पूरी संभावनाओं को सामने लाने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

उन्नत कृषि महोत्सव का भव्य समापन, किसानों के साथ कृषि बदलाव का नया संकल्प

शिवराज सिंह चौहान की मांग पर नितिन गडकरी की बड़ी सौगात, रायसेन रिंग रोड और सौंदर्यीकरण कार्यों को मिली मंजूरी

किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता और हाइड्रोजन दाता भी बनेगा- नितिन गडकरी

एआई, ड्रोन, नैनो यूरिया और नवाचार से घटेगी लागत, बढ़ेगा उत्पादन- नितिन गडकरी

जल संरक्षण, डेयरी, मत्स्य और प्रोसेसिंग से बढ़ेगी किसानों की आमदनी- नितिन गडकरी

यह समापन नहीं, नई शुरूआत है; रोडमैप को जमीन पर उतारेंगे- शिवराज सिंह चौहान

बीज से बाजार तक की योजना पर अमल के लिए बनेगी टास्क फोर्स- शिवराज सिंह चौहान

किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे- शिवराज सिंह चौहान

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कृषि मेले 'उन्नत कृषि महोत्सवह्व का रायसेन में अत्यंत उत्साह, उमंग, नवाचार और हजारों किसानों की गरिमामयी उपस्थिति के बीच भव्य समापन हुआ। समापन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जहां सड़क विकास, कृषि तकनीक, जल संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि का व्यापक विजन रखा, वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बीज से बाजार तक तैयार रोडमैप को जमीन पर उतारने का दृढ़ संकल्प दोहराया।

शिवराज सिंह चौहान द्वारा रखी गई क्षेत्रीय मांगों पर महत्वपूर्ण घोषणाएँ

रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर आयोजित 'उन्नत कृषि महोत्सवह्व के समापन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रखी गई क्षेत्रीय मांगों पर महत्वपूर्ण घोषणाएँ करते हुए विकास की नई सौगात दी। उन्होंने रायसेन रिंग रोड/पूर्वी बायपास के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने, संबंधित डीपीआर तैयार करने, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए जाने और पुलों के सौंदर्यीकरण संबंधी मांगों पर सकारात्मक सहमति व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य सड़क संबंधी प्रस्तावों पर भी जो संभव सहयोग होगा, वह किया जाएगा।

ज्ञान को संपत्ति में बदलना आज कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है

अपने संबोधन में श्री गडकरी ने कहा कि वे इस कार्यक्रम में मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि किसान के रूप में

आए हैं। उन्होंने कहा कि खेती का भविष्य अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर स्टेशन, सैटेलाइट आधारित सूचना, ड्रोन, नैनो यूरिया और आधुनिक कृषि तकनीकों से जुड़ चुका है, इसलिए किसानों को समय के साथ बदलना होगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और ज्ञान को संपत्ति में बदलना आज कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने किसानों से इनोवेशन, रिसर्च, सफल प्रयोगों और तकनीक-आधारित खेती को अपनाने का आह्वान किया, ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन संभव हो सके।

श्री गडकरी ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, डामर दाता और हाइड्रोजन दाता भी बनेगा। उन्होंने कहा कि कृषि अवशेष, पराली, बायोमास, इथेनॉल, सीएनजी और हाइड्रोजन के माध्यम से किसानों के लिए आय के नए रास्ते खुलेंगे, आयात घटेगा और गांवों की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी।

जल संरक्षण पर विशेष बल

जल संरक्षण पर विशेष बल देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि दौड़ते हुए पानी को चलने के लिए, चलने वाले पानी को रुकने के लिए और रुके हुए पानी को जमीन को पिलाने के लिए लगाना होगा। उन्होंने 'गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर मेंह्व का संदेश देते हुए कहा कि जैसे पैसा बैंक में जमा किया जाता है, वैसे ही पानी को जमीन में डिपॉजिट करना होगा।

उन्होंने कहा कि जहां सिंचाई का पानी सीधे नहीं पहुँच सकता, वहां जल संरक्षण की संरचनाएँ बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।

उन्होंने डेयरी, मत्स्य पालन और ब्लू इकोनॉमी को किसानों की आय बढ़ाने के बड़े माध्यम बताते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। श्री गडकरी ने कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि प्रोसेसिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, प्री-कूलिंग सिस्टम और वैल्यू एडिशन की मजबूत व्यवस्था भी बनानी होगी। उन्होंने कहा कि जब बाजार में उत्पादन अधिक होता है तो कीमतें गिर जाती हैं, इसलिए भंडारण और प्रसंस्करण की मजबूत व्यवस्था किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए आवश्यक है।

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे मेले में लगे स्टॉल, मशीनरी प्रदर्शन, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, हाइड्रोपोनिक्स, एक एकड़ खेती के मॉडल, बकरी पालन, मछली पालन और अन्य तकनीकी सत्रों को देखकर जाएँ, सीखकर जाएँ और उसे खेत में लागू करें। उन्होंने कहा कि यही ज्ञान, यही तकनीक और यही प्रयोग किसानों का भविष्य बदलेंगे, गांवों को समृद्ध बनाएंगे और स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज की दिशा को मजबूत करेंगे।

शिवराज सिंह के मुख्यमंत्रीत्व कार्यकाल की म.प्र. की कृषि उपलब्धियों की सराहना

श्री गडकरी ने शिवराज सिंह के मुख्यमंत्रीत्व कार्यकाल में मध्य प्रदेश की कृषि उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि किसानों को उन्नत बनाने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद महत्वपूर्ण हैं और यह महोत्सव किसानों को भविष्य की नई प्रेरणा देने वाला सिद्ध होगा।

यह समापन नहीं, बल्कि नई शुरूआत है

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'उन्नत कृषि महोत्सवह्व कोई कर्मकांड नहीं है और यह समापन नहीं, बल्कि नई शुरूआत है। उन्होंने कहा कि चार दिनों तक चले इस आयोजन ने किसानों के लिए पाठशाला का काम किया, जहाँ मिट्टी की महक, मशीन की शक्ति, नवाचार, तकनीक और विकास का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री चौहान ने कहा कि इस क्षेत्र की माटी, जलवायु, जल उपलब्धता और संसाधनों के आधार पर बीज से बाजार तक का विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस रोडमैप में यह तय किया गया है कि इस क्षेत्र में कौन-कौन सी फसलें, फल और सब्जियाँ अच्छी हो सकती हैं और उनके उत्पादन, प्रोसेसिंग तथा मार्केटिंग की संपूर्ण योजना कैसे बनेगी।

दलहन और बागवानी क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि अच्छे बीज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर ब्लॉक में बीज ग्राम बनाए जाएंगे, दलहन और बागवानी क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा और इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी की एक-एक बूंद का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा तथा कस्टम हायरिंग सेंटर और पंचायतों में मशीन बैंक बनाए जाएंगे, ताकि किसानों को आधुनिक मशीनें आसानी से मिल सकें। श्री चौहान ने कहा कि अच्छी नर्सरी और क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, एफपीओ को मजबूत किया जाएगा, बैक हाउस और कोल्ड हाउस बनाए जाएंगे और किसानों को उत्पादन से बाजार तक बेहतर ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एकीकृत खेती के मॉडल के माध्यम से छोटे खेत के टुकड़े पर भी अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है और सरकार किसानों की आय बढ़ाकर ही चैन की सांस लेगी।

रोडमैप की मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे रोडमैप की मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी तथा राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि जो संकल्प लिए गए हैं, वे केवल घोषणा बनकर न रह जाएँ, बल्कि पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरें।

डीआरडीओ बिहार के मोतिहारी में आयोजित होने वाली विशाल प्रदर्शनी के दौरान देश की अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत पहल का भव्य प्रदर्शन करेगा

(जीएनएस)।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) 15 से 18 अप्रैल, 2026 तक बिहार के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाली भव्य प्रदर्शनी के दौरान अपनी अत्याधुनिक तकनीकों, उन्नत रक्षा प्रणालियों और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में किए जा रहे सशक्त प्रयासों का व्यापक प्रदर्शन करेगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन संसद सदस्य एवं रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह द्वारा किया जाएगा। इस प्रदर्शनी की विषयवस्तु 'शांति, सत्य और विज्ञान का संगम - सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर' रखी गई है।

प्रदर्शनी में उन्नत रक्षा प्रणालियों से युक्त अत्याधुनिक मॉडलों और स्वदेशी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का आकर्षक प्रदर्शन किया जाएगा। इनमें एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (एईडब्ल्यूएंडसी) सिस्टम, आकाश सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल, आकाश-एनजी (नई पीढ़ी) मिसाइल लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, एंटी-सैटेलाइट (ए-सैट) मिसाइल, नाग एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल, प्रलय मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एमपीएटीजीएम), एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस), पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (एमएलआरएस), मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) अर्जुन एमके-क&क्क, भारतीय लाइट टैंक (आईएलटी), मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम, ड्रोन डिटेक्शन रडार, उत्तम एईएसए रडार, होलोग्राफिक साइट, ऑटोमैटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म (एसीएडीए) सिस्टम, केमिकल एजेंट मॉनिटर (सीएएम), केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर (सीबीआरएन) जल शुद्धिकरण प्रणाली (सीबीआरएन-डब्ल्यूपीएस), बैक पैक-5केजी, ए

नबीसी सूट एमके-श, मल्टी-फंक्शनल माउंटेड गन सिस्टम (एमजीएस), व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (डब्ल्यूएचएपी) के लिए कंपोजिट आर्मर, कावेरी इंजन का रैपिड प्रोटोटाइप मॉडल, कावेरी इंजन का स्पेशल रियलिटी डिस्प्ले, ब्लास्ट प्रोटेक्शन सूट, बैलिस्टिक हेलमेट, नौसेना स्टील और अन्य सामग्री प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आमजन, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करना और उन्हें डीआरडीओ द्वारा विकसित उन अत्याधुनिक तकनीकों एवं प्रणालियों को करीब से देखने व समझने का अवसर प्रदान करेगा, जो देश की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बना रही हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

राष्ट्रीय कैडेट कोर ने कैडेटों के लिए राष्ट्रव्यापी साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के सहयोग से कैडेटों को साइबर जागरूकता, डिजिटल स्वच्छता और व्यावहारिक साइबर सुरक्षा कौशल में संरचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स और एनआईईएलआईटी के महानिदेशक डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी की उपस्थिति में एनसीसी और एनआईईएलआईटी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

पहले चरण में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम होगा। यह एक 15 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल है। इसे डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, साइबर स्वच्छता और साइबर खतरों के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह चरण देश भर के सभी पंजीकृत एनसीसी कैडेटों के लिए खुला रहेगा और इसे एनआईईएलआईटी डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

दूसरें चरण में साइबर रक्षा कार्यक्रम होगा। यह एक गहन 60 घंटे का ऑफलाइन प्रशिक्षण है। इसे योग्यता-आधारित स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से चयनित कैडेटों के लिए तैयार किया गया है। इस चरण में व्यावहारिक प्रशिक्षण, वास्तविक जीवन के सिमुलेशन और साइबर सुरक्षा उपकरणों और तकनीकों के व्यावहारिक अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे कैडेट साइबर खतरों को प्रभावी ढंग से पहचानने और उनसे निपटने में सक्षम होंगे।

इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर साइबर जागरूकता फैलाने, सुरक्षित डिजिटल तौर-तरिकों को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा पहलों का समर्थन करने में योगदान देने के लिए प्रशिक्षित एनसीसी साइबर कैडेटों का एक समूह तैयार करना है। यह कार्यक्रम डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप भी है।

दिल्ली शराब नीति से जुड़े केस में दिल्ली हाई कोर्ट कर रहा सुनवाई, अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे अपनी पैरवी

(जीएनएस)।

दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। यह याचिका दिल्ली शराब नीति से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देती है।

इस मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब केजरीवाल ने स्वयं न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा से मामले की सुनवाई से हटने, जिसे न्यायिक शब्दावली में 'रिक्यूजल' कहते हैं, का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया। वह व्यक्तिगत तौर पर अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं।

इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल आज हाई कोर्ट जाएंगे। उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई दोपहर में होगी। अरविंद केजरीवाल खुद अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष अपनी पुनर्विचार याचिका दायर की है।

रिक्यूजल आवेदन पर पहली सुनवाई 6 अप्रैल को हुई थी, जहाँ न्यायालय ने सीबीआई से केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा था। 6 अप्रैल की सुनवाई के दौरान, सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने इस रिक्यूजल याचिका का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया कि केजरीवाल का आवेदन "आधारहीन आरोपों" पर आधारित है। सीबीआई ने भी रिक्यूजल आवेदन का विरोध करते हुए अपनी औपचारिक प्रतिक्रिया दाखिल कर दी है।

न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा कि निचली अदालत ने जिस तरह सीबीआई ने गवाहों को सरकारी गवाह बनाया, "उनका आचरण एक सुनियोजित परिणाम साबित करने वाला था।" उन्होंने आगे कहा, "अंततः निचली अदालत ने मुझे पूरी तरह से आरोपमुक्त कर दिया, जिसके निष्कर्ष इस अदालत के निष्कर्षों के बिल्कुल विपरीत थे, इसलिए मेरे मन में एक शंका है।"

इस पर न्यायमूर्ति शर्मा ने पलटवार करते हुए पूछा, "आपकी दलीलें क्या हैं? क्योंकि आपने कहा है कि निचली अदालत के उस फैसले को गलत बताया गया है... जिस वक्त मैंने फैसला किया उस समय इस अदालत (ट्रायल कोर्ट) का तो फैसला हुआ नहीं था। निचली अदालत के आदेश पर हम तब जाएंगे जब वे इस पर निर्णय लेंगे। आज हम सिर्फ रिक्यूजल के मुद्दे पर आपकी बात सुन रहे हैं।"

केजरीवाल ने आगे दलील दी कि सरकारी गवाहों से जुड़ा एक मुद्दा उठा था, जिस पर अदालत की अपनी एक 'फाइंडिंग' है। उन्होंने कहा कि "इस पर भी एक अंतिम फाइंडिंग दे दी गई थी। मुझे लगभग भ्रष्ट घोषित कर दिया गया था। मुझे लगभग दोषी घोषित कर दिया गया था। बस सजा सुनानी रह गई थी।" पीठ ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा, "मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह आपकी सोच है।"

केजरीवाल ने बताया कि इस न्यायालय के सामने पहले भी पांच मामले आ चुके हैं। उनके स्वयं की गिरफ्तारी का मामला, संजय सिंह, के. कविता और अमन ढाल के जमानत आवेदन शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इन मामलों में अदालत द्वारा की गई टिप्पणियाँ "फैसले के समान" थीं, जो एक तरह से अंतिम निर्णय का आभास देती थीं।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस संबंध में 'सत्येंद्र जैन बनाम ईडी' मामले में इसी अदालत के एक फैसले का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उस मामले में जमानत की सुनवाई चल रही थी और छह दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी थी, जब ईडी ने अचानक न्यायाधीश पर 'भय या पूर्वाग्रह की आशंका' जताई। जिला न्यायाधीश ने इसे स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय ने भी अनुमति दे दी।

केजरीवाल ने बताया कि उस मामले और उनके मामले में काफी समानताएं हैं। उन्होंने कहा कि उस मामले में न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि "सवाल न्यायाधीश की ईमानदारी का नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता के मन में उत्पन्न आशंका का है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका मामला भी ठीक वैसा ही है, जहाँ न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा पर नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता के मन की आशंका पर विचार किया जाना चाहिए।

केजरीवाल ने न्यायाधीशों के रिक्यूजल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 'रणजीत ठाकुर बनाम भारत संघ' फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें साफ तौर पर कहा है कि "न्यायाधीश को यह नहीं देखना है कि वह पक्षपाती नहीं हैं, बल्कि अगर पार्टी के मन में पक्षपात की शंका है, तो रिक्यूजल का मामला बनता है।" इसी कारणवश, केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दर्ज कराई।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि "मेरे मन में जो आशंका है वह मेरे और अदालत के बीच का मामला है। सीबीआई को इस मामले में पार्टी नहीं बनाया जाना चाहिए।" केजरीवाल ने अपनी बात दोहराई कि उनके मन में न्याय को लेकर आशंका है, और यह मामला केवल अदालत और उनके बीच का है।

केजरीवाल ने बताया कि 9 मार्च का आदेश आने पर "मेरा दिल बैठ गया।" उन्हें पूर्वाग्रह की गंभीर आशंकाएं थीं, जिसके चलते उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा। मुख्य न्यायाधीश ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने यह आवेदन न्यायालय में दाखिल किया।

उन्होंने 9 मार्च के आदेश पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, "9 मार्च को जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सीबीआई के अलावा कोई मौजूद नहीं था। एकतरफा (एक्स-पार्टे), बिना किसी की सुनवाई किए, बिना किसी का जवाब लिए इस अदालत ने आदेश पारित किया कि प्रथम दृष्टया आदेश गलत है।" केजरीवाल ने हैरानी व्यक्त की कि जिस आदेश को निचली अदालत ने पूरे दिन की सुनवाई और 40,000 से अधिक पृष्ठों के दस्तावेजों को पढ़ने के बाद पारित किया था, उसे उच्च न्यायालय ने मात्र पांच मिनट की सुनवाई के बाद "त्रुटिपूर्ण" घोषित कर दिया।

लखनऊ के मलिहाबाद में विपरीत दिशा से आ रही कार ने बाइक में मारी टक्कर, महिला की मौत; तीन घायल

पुलिस ने घायलों को ट्रामा सेंटर पहुंचाया, मृतका के शव को कब्जे में लिया

मलिहाबाद थाना क्षेत्र का हादसा, कार चालक के खिलाफ की जा रही कार्रवाई

मलिहाबाद। (जीएनएस)। सड़क पर लापरवाही और तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। मलिहाबाद में विपरीत दिशा से आ रही कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक मासूम समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस ने घायलो को अस्पताल पहुंचाया और स्थिति को सामान्य किया।

मनकौटी निवासी तालिब अपनी भाभी 35 वर्षीय जुल्फी और पांच वर्षीय भतीजे जुहैब को मायके छोड़ने के लिए उन्नाव के नियाज अली खेड़ा जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वह विपरीत दिशा से सफर कर रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक भतोइया गांव स्थित आरआर लान के पास पहुंची, सामने से तेज रफ्तार में आ रही स्विफ्ट कार ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों लोग सड़क किनारे खाई में जा गिरे। वहीं कार भी अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। हादसे में तालिब, जुल्फी और जुहैब गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार सवार संडीला के काजीपुर निवासी रोहित को भी गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।

2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु में वर्षा का दीर्घकालिक पूवार्नुमान

देश में 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसमी (जून से सितंबर) वर्षा के सामान्य से कम रहने की संभावना है (दीर्घकालीन औसत (एलपीए) का 95-90%)

देश में मौसमी वर्षा एलपीए का 92% रहने की संभावना है। इसमें मॉडल त्रुटि ± 5% है

1971-2020 की अवधि के आधार पर देश में मौसमी वर्षा का एलपीए 87 सेंटीमीटर है

भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में कमजोर ला नीना जैसी स्थितियां ई एन एस ओ-तटस्थ स्थितियों में परिवर्तित हो रही हैं

उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में वायुमंडलीय परिसंचरण विशेषताएं कमजोर ला नीना जैसी स्थितियों के अनुरूप बनी हुई हैं

मानसून मिशन जलवायु पूवार्नुमान प्रणाली (एमएमसीएफएस) दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अल नीनो स्थितियों के तैयार होने का सुझाव देती है

हिंद महासागर में तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) स्थितियां मौजूद हैं और नवीनतम जलवायु मॉडल पूवार्नुमान इंगित करता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के अंत तक सकारात्मक आईओडी स्थितियां विकसित होने की संभावना है

उत्तरी गोलार्ध में अंतिम तीन महीनों (जनवरी से मार्च 2026) के दौरान हिम आवरण का विस्तार

उत्तरी गोलार्ध और यूरेशिया में सर्दियों और वसंत ऋतु में बर्फ की मात्रा सामान्य से थोड़ी कम रही। देश में होने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा के साथ इसका सामान्यतः विपरीत संबंध है

मौसम विभाग मई 2026 के अंतिम सप्ताह में मानसून मौसम की वर्षा के अद्यतन पूवार्नुमान जारी करेगा

(जीएनएस)।

2003 से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) देश भर में होने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम (जून-सितंबर) वर्षा के औसत पूवार्नुमान को दो चरणों में जारी करता आ रहा है। पहले चरण का पूवार्नुमान अप्रैल में और दूसरे चरण का अद्यतन पूवार्नुमान मई के अंत तक जारी किया जाता है। 2021 में आईएमडी ने वर्तमान दो-चरणीय पूवार्नुमान रणनीति में संशोधन करते हुए, देश भर में होने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा के मासिक और मौसमी पूवार्नुमान जारी करने के लिए एक नई रणनीति शुरू की। नई रणनीति में गतिशील और सांख्यिकीय दोनों पूवार्नुमान प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। गतिशील पूवार्नुमान प्रणाली में आईएमडी के मानसून मिशन जलवायु पूवार्नुमान प्रणाली (एमएमसीएफएस) सहित विभिन्न वैश्विक जलवायु पूवार्नुमान केंद्रों के वैश्विक जलवायु मॉडल (सीजीसीएम) पर आधारित मल्टी-मॉडल एन्सेम्बल (एमएमई) पूवार्नुमान प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

नई एलआरएफ रणनीति के अनुसार अप्रैल के मध्य में जारी किए गए पहले चरण के पूवार्नुमान में पूरे देश के लिए मात्रात्मक और पूवार्नुमान और देश भर में मौसमी (जून-सितंबर) वर्षा की तृतीय श्रेणियों (सामान्य से ऊपर, सामान्य और सामान्य से नीचे) के लिए पूवार्नुमानों का स्थानिक वितरण शामिल है।

मई के अंत में जारी किए गए दूसरे चरण के पूवार्नुमान में अप्रैल में जारी किए गए मौसमी वर्षा पूवार्नुमान के अद्यतन के साथ-साथ भारत के चार समरूप क्षेत्रों (उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत, दक्षिणी प्रायद्वीप और उत्तर-पूर्व भारत) और मानसून कोर जोन (एमसीजेड) में मौसमी वर्षा के पूवार्नुमान शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे चरण के पूवार्नुमान के दौरान देश के लिए मात्रात्मक और पूवार्नुमान और जून की वर्षा की तृतीय श्रेणियों (सामान्य से अधिक, सामान्य और सामान्य से कम) के लिए पूवार्नुमानों का स्थानिक वितरण भी जारी किया जाता है।

उपरोक्त पूवार्नुमानों के क्रम में अगले एक महीने के लिए मासिक वर्षा पूवार्नुमान क्रमशः जून, जुलाई और अगस्त के अंत में जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त देश के लिए मात्रात्मक और पूवार्नुमान और मौसमी वर्षा के दूसरे भाग के लिए तृतीय श्रेणियों के पूवार्नुमानों का स्थानिक वितरण जुलाई के अंत में अगस्त के पूवार्नुमान के साथ जारी किया जाता है।

1. देश भर में वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (जून-सितंबर) में होने वाली वर्षा का पूवार्नुमान।

गतिशील और सांख्यिकीय दोनों मॉडलों पर आधारित पूवार्नुमान से पता चलता है कि मात्रात्मक रूप से मानसून की मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का 92% होने की संभावना है। इसमें मॉडल त्रुटि ± 5% है। 1971-2020 की अवधि के लिए देश भर में मौसमी वर्षा का एलपीए 87 सेंटीमीटर है।

देश भर में मौसमी (जून से सितंबर) वर्षा के लिए पांच श्रेणियों का पूवार्नुमान नीचे दिया गया है। पूवार्नुमान से पता चलता है कि सामान्य से कम और अपर्याप्त वर्षा दोनों श्रेणियों की संभावनाएँ उनके संबंधित जलवायु संबंधी संभावनाओं से अधिक हैं। सामान्य से अधिक और अत्यधिक वर्षा श्रेणियों की पूवार्नुमानित संभावनाएँ उनके संबंधित जलवायु संबंधी संभावनाओं से कम हैं। कुल मिलाकर, देश भर में दक्षिण-पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा सामान्य से कम (एलपीए का 90-95%) रहने की सबसे अधिक संभावना है।

2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसमी वर्षा के लिए एमएमई का पूवार्नुमान अप्रैल की प्रारंभिक स्थितियों के आधार पर और भारतीय मानसून क्षेत्र में उच्चतम पूवार्नुमान कौशल वाले जलवायु मॉडलों के एक समूह का उपयोग करके तैयार किया गया था।

जून से सितंबर तक की मौसमी वर्षा के लिए संभाव्यता पूवार्नुमानों की तृतीय श्रेणियों (सामान्य से अधिक, सामान्य और सामान्य से कम) का स्थानिक वितरण चित्र 1 में दर्शाया गया है। स्थानिक वितरण से पता चलता है कि पूर्वोत्तर, उत्तर-पश्चिम और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम मौसमी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। यहां सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। भूमि क्षेत्र के भीतर सफेद रंग से चिह्नित क्षेत्र मॉडल से कोई संकेत नहीं दर्शाते हैं।

2. भूमध्यरेखीय प्रशांत और हिंद महासागरों में समुद्र की सतह के तापमान (एसएसटी) की स्थितियाँ

वर्तमान में भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में कमजोर ला नीना जैसी स्थितियाँ ई एन एस ओ-तटस्थ स्थितियों में परिवर्तित हो रही हैं। हालाँकि उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में कुछ वायुमंडलीय परिसंचरण विशेषताएँ कमजोर ला नीना जैसी स्थितियों के अनुरूप बनी हुई हैं। मानसून मिशन जलवायु पूवार्नुमान प्रणाली के नवीनतम पूवार्नुमानों से संकेत मिलता है कि अप्रैल से जून 2026 के मौसम के दौरान ई एन एस ओ-तटस्थ स्थितियाँ जारी रहने की सबसे अधिक संभावना है। मानसून मिशन जलवायु पूवार्नुमान प्रणाली दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अल नीनो की स्थितियों के विकसित होने का संकेत देती है।

वर्तमान में हिंद महासागर पर तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) की स्थिति मौजूद है और नवीनतम जलवायु मॉडल पूवार्नुमान से संकेत मिलता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के अंत तक सकारात्मक आईओडी की स्थिति विकसित होने की संभावना है।

प्रशांत और हिंद महासागरों में समुद्र की सतह के तापमान (एसएसटी) की स्थिति का भारतीय मानसून पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) इन महासागरीय बेसिनों में समुद्र की सतह की स्थितियों के विकास की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहा है।

3. उत्तरी गोलार्ध पर हिम आवरण

पिछले तीन महीनों (जनवरी से मार्च 2026) के दौरान उत्तरी गोलार्ध में हिमपात का विस्तार सामान्य से थोड़ा कम रहा। उत्तरी गोलार्ध और यूरेशिया में शीतकालीन और वसंतकालीन हिमपात का विस्तार, देश में होने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा के साथ सामान्यतः विपरीत संबंध रखता है। 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (जून-सितंबर) के दौरान भारत में मौसमी वर्षा की तृतीय श्रेणियों* (सामान्य से कम, सामान्य और सामान्य से अधिक) का पूवार्नुमान। यह चित्र सबसे संभावित श्रेणियों और उनकी संभावनाओं को दशार्ता है। सफेद छायांकित क्षेत्र मॉडल से कोई संकेत न मिलने का प्रतिनिधित्व करते हैं। (*तृतीय श्रेणियों की जलवायु संबंधी संभावनाएँ समान हैं प्रत्येक की 33.33%)।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने नवप्रवर्तकों को एबी पीएम-जेएवाई ऑटो-अजूडकेशन हैकाथॉन 2026 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है

एबी पीएम-जेएवाई ऑटो-अजूडकेशन हैकाथॉन का उद्देश्य मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकृत, मैन्युअल कार्य को कम करने, दावों के निपटान में तेजी लाने और मापनीय, भविष्य के लिए निणेर्यों की रूपरेखा बनाने के लिए अभिनव डिजिटल समाधान तैयार करना है

पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 अप्रैल है, अब तक कुल 2,600 से अधिक प्रतिभागियों का पंजीकरण हो चुका हैं; मास्टरक्लास श्रृंखला 13 अप्रैल से शुरू होगी

(जीएनएस)।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई), सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा कार्यान्वित प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना देश में डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन को गति प्रदान कर रही है और प्रतिदिन लगभग 50,000 दावों का निपटान 1,900 से अधिक उपचार पैकेजों के तहत कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर

दावों के निपटान में गति, सटीकता और अनुपालन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में 15-20 प्रतिशत दावों का निपटान स्वतः हो जाता है, फिर भी एक ऐसे समाधान की आवश्यकता बनी हुई है जो सभी पैकेजों के लिए उपयुक्त हो और सभी पर लागू हो सके।

दावों की संख्या और जटिलता को देखते हुए विभिन्न प्रकार के उपचारों और दस्तावेज स्वरूपों को संभालने में सक्षम एक उन्नत स्वचालित निर्णय प्रणाली की आवश्यकता बढ़ रही है। स्वचालन, एआई-आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने, मानकीकृत दस्तावेजीकरण का तत्‍क्षण लाभ उठाकर दावों की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जा सकता है, जिससे अधिक सुसंगत और पारदर्शी परिणाम शीघ्र प्राप्त हो सकें।

एबी पीएम-जेएवाई ऑटो-अजूडकेशन हैकाथॉन का उद्देश्य ऐसे अभिनव डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देना है जो मौजूदा एबी पीएम-जेएवाई बुनियादी ढांचे के साथ सहजता से एकीकृत हों, मैन्युअल प्रयासों को कम करें, निपटान समय को कम करें और पूरे इकोसिस्‍टम के लिए एक मापनीय, भविष्य के लिए निर्णय ढांचा तैयार करें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को एबी पीएम-जेएवाई ऑटो-अजूडकेशन हैकाथॉन 2026 के लिए शानदार प्रतिक्रिया मिली है, अब तक देश भर से 2,600 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है।

पंजीकरण की अंतिम तिथिः 13 अप्रैल 2026

इच्छुक छात्र, शोधकर्ता, डेवलपर, पेशेवर, स्टार्टअप और नवप्रवर्तक 13 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

तीन मास्टरक्लास सत्र 13 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे

प्रतिभागियों को चुनौतियों को समझने और संभावित समाधानों की पहचान करने में सहायता करने के लिए एनएचए 13 अप्रैल 2026 से तीन मास्टरक्लास श्रृंखला का आयोजन करेगा। सत्रों में दावा निपटान प्रणाली, हैकाथॉन से प्रमुख अपेक्षाएं और डिजिटल स्वास्थ्य में नवाचार के उभरते अवसरों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की जाएगी।

मास्टरक्लास श्रृंखला का कार्यक्रम इस प्रकार हैः

सत्र 1ः 13 अप्रैल 2026` दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

सत्र 2ः 15 अप्रैल 2026` दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

सत्र 3ः 16 अप्रैल 2026` दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

सभी सत्रों का सीधा प्रसारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आधिकारिक यूट्यूब चैनल @अ८४रैंल्लठऌअ पर भी किया जाएगा।

आईआईएससी बेंगलुरु में भव्य समापन समारोह

हैकथॉन का समापन 8-9 मई, 2026 को बेंगलुरु स्थित प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान में होगा, जहां विजेता टीमें स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र के दिग्‍गजों की निर्णायक समिति के समक्ष अपने समाधान प्रस्तुत करेंगी। विजेताओं को प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए 5 लाख 3 लाख और 2 लाख रुपये के आकर्षक नकद पुरस्कार के साथ-साथ एनएचए के साथ संभावित सहयोग का अवसर भी मिलेगा।

डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार को आगे बढ़ाना

यह हैकाथॉन एनएचए के भविष्य के लिए तैयार डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों के विकास के लिए नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। जो दक्षता तथा पारदर्शिता को मजबूत बनाकर लाभार्थियों और प्रदाताओं दोनों के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण को बेहतर बनाता है।

प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री ने परोपकारी शक्तियों को पोषित करने पर एक संस्कृत सुभाषितम् साझा किया

नई दिल्ली, (जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जलियांवाला बाग के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि उनका बलिदान हमारे लोगों के अडिग साहस की एक सशक्त याद दिलाता है।

प्रधानमंत्री ने आज एक संस्कृत सुभाषितम् भी साझा किया, जिसमें समाज में परोपकारी शक्तियों के पोषण का आह्वान किया गया है, जो राष्ट्र को समृद्ध, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाती हैं, साथ ही विभाजन, अन्याय और असंतोष उत्पन्न करने वाली विनाशकारी शक्तियों का दृढ़ता से प्रतिरोध करने का संदेश दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखाः

'आज के दिन हम जलियांवाला बाग के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका बलिदान हमारे लोगों के अडिग साहस की एक सशक्त याद दिलाता है। उनके द्वारा प्रदर्शित किया गया साहस और दृढ़ संकल्प पीढ़ियों को स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहता है। 'जलियांवाला बाग नरसंहार के सभी अमर बलिदानियों को मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। विदेशी हुकूमत की बर्बरता के खिलाफ उनके अदम्य साहस और स्वाभिमान की गाथा देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी।

इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्।

अपघ्नन्तो अराव्णः॥"

हे परिश्रमी लोगों! अपने समाज में उन परोपकारी शक्तियों का पोषण करें, जो राष्ट्र को समृद्ध, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाती हैं। साथ ही, उन विनाशकारी शक्तियों का दृढ़ता से प्रतिरोध करें, जो समाज में विभाजन, अन्याय

24 साल बाद लखनऊ स्थित विधान भवन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पुरानी यादों को किया ताजा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 साल बाद लखनऊ के विधान भवन का दौरा किया। उन्होंने वहां हुए व्यापक नवाचारों, डिजिटल गैलरी और आधुनिक व्यवस्थाओं की सराहना ..

रविवार को विधान भवन के निरीक्षण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनकी तस्वीर भेंट करते विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना

राजनाथ सिंह ने 24 साल बाद विधान भवन का भ्रमण किया।

उन्होंने डिजिटल गैलरी और आधुनिक व्यवस्थाओं की सराहना की।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात कर सेल्फी ली।

लखनऊ। (जीएनएस)। विधान भवन में रविवार दोपहर को एक अलग परिदृश्य उभरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 साल बाद विधान भवन में भ्रमण करते नजर आए। उन्होंने विधान भवन के विभिन्न हिस्सों में किए गए बदलावों एवं प्रयोगों की सराहना की। विधान भवन में अपने बीते हुए पलों का स्मरण सबसे साझा किया।

दोपहर करीब 12 बजे राजनाथ सिंह विधान भवन पहुंचे, जहां सतीश महाना ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने यहां किए गए व्यापक नवाचारों, सुदृढ़ व्यवस्थाओं तथा आधुनिकीकरण कार्यों की सराहना की।

सबसे पहले डिजिटल गैलरी का अवलोकन किया, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा के गौरवमयी इतिहास पर आधारित एक विशेष फिल्म देखी। उन्होंने कहा कि यहां किए गए ये नवाचार जनप्रतिनिधियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जिससे विधायी कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।

रक्षा मंत्री ने परिसर में विकसित विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने वर्चुअल हेलिकाप्टर अनुभव, आधुनिक गलियारों तथा नवीन व्यवस्थाओं को देखा। समिति कक्ष, टंडन हाल, सुसज्जित दर्शक दीर्घा, मंडप कक्ष, गैलरी में प्रदर्शित महापुरुषों के चित्रों का अवलोकन किया।

मीडिया कक्ष तथा ऐतिहासिक महत्व के भित्तिचित्र को भी देखा। प्रवेश द्वार और समग्र परिसर के आकर्षक स्वरूप की प्रशंसा की। राजनाथ सिंह ने विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ एक डिजिटल आत्म-चित्र भी लिया। उन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन पर आधारित एक विशेष पुस्तक भेंट की गई।

लखनऊ में रेलवे और पीडब्लूडी के बीच फंसा कटाई वाला रेलवे पुल, रोज लगता है लंबा जाम

लखनऊ में सोमनाथ द्वार पर नया कटाई वाला पुल आठ महीने से बंद है, जिससे भारी जाम लग रहा है।

रेलवे और पीडब्ल्यूडी के बीच एप्रोच रोड निर्माण को लेकर विवाद है और नया कटाई वाला पुल आठ माह से बंद।

पीडब्ल्यूडी द्वारा एप्रोच रोड न बनने से देरी।

सोमनाथ द्वार पर भीषण यातायात जाम।

लखनऊ। (जीएनएस)। वीआईपी मूवमेंट के कारण सोमवार को सोमनाथ द्वार से लॉरेटो चौराहा की ओर जाने वाला यातायात जाम से जूझता रहा। करीब आठ महीने पहले तैयार किया गया पुल बैरिकेडिंग से बंद रहा और वाहन पुराने पतले पुल होकर रेंगते रहें। नया पुल रेलवे और पीडब्लयूडी के बीच फंस गया है। पीडब्ल्यूडी को नए पुल से रेलवे ऑफिसर्स क्लब मोड़ तक करीब 350 मीटर का एप्रोच रोड बनाना है। लेकिन यह काम पूरा न होने के कारण

नए पुल पर यातायात शुरू ही नहीं हो पा रहा है।

सोमनाथ द्वार चौराहा पर सुलतानपुर रोड और रायबरेली रोड का यातायात मिलता है और दो लेन के कटाई वाला पुल से होकर रेलवे ऑफिसर्स क्लब होते हुए लारेटो चौराहा की ओर जाता है। सुबह नौ से 11 और शाम छह से रात आठ बजे तक यातायात का दबाव अधिक होने से इस पुराने पुल पर जाम की स्थिति बनी रहती है।

मौजूदा कटाई वाला पुल का निर्माण लखनऊ में रेल नेटवर्क बिछाते समय सन 1872 में किया गया था। रेलवे अब जबकि लखनऊ स्टेशन से दिलकुशा तक नार्थ व साउथ को दो की जगह चार लाइन का बना रहा है, ऐसे में कटाई वाला पुल के चौड़ीकरण की भी जरूरत थी। रेलवे ने पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर कटाई वाला पुल के चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार किया था।

इसके तहत रेल लाइन के ऊपर चार लेन का पुल बनाने का काम 14.50 करोड़ रुपये की लागत से पिछले साल अगस्त में पूरा हो गया था। पीडब्ल्यूडी को 350 मीटर लंबा एप्रोच रोड़ बनाने के लिए रेलवे ने 3.50 करोड़ रुपये दे दिए हैं। हालांकि आठ महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद एप्रोच रोड नहीं बन पा रही है। इस कारण पुल को रेलवे शुरू नहीं कर रहा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पिछले सप्ताह पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को एक पत्र फिर से भेजा गया है।

प्रदेश में पहली बार हुआ हृदय प्रत्यारोपण, दिल्ली की डोनर का दिल एंबुलेंस से पहुंचा लखनऊ; इस तरह हुआ ऑपरेशन

लखनऊ (जीएनएस)। लखनऊ पीजीआई ने सोमवार को एक नया इतिहास रच दिया है। यूपी में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया गया।

संजय गांधी पीजीआई ने चिकित्सा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्थान में प्रदेश का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया। दिल्ली निवासी डोनर से प्राप्त दिल ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लखनऊ लाया गया। यहां सीतापुर निवासी व्यक्ति को यह दिल प्रत्यारोपित किया गया।

संस्थान के निदेशक प्रो. आरके धीमन ने बताया कि संस्थान में हृदय प्रत्यारोपण की तैयारी पहले ही की जा चुकी थीं। डोनर न होने की वजह से अभी तक इसकी शुरूआत नहीं हुई थी। दिल्ली निवासी व्यक्ति के परिवार वालों ने ब्रेन डेड होने के बाद उसके अंगदान करने का फैसला किया था। अंगदाता के अन्य अंग, लिवर और गुर्दे, दिल्ली में ही प्रत्यारोपित किए गए। हृदय को त्वरित एयर एंबुलेंस के माध्यम से लखनऊ लाया गया, जिसके बाद ग्रीन कॉरिडोर का उपयोग किया गया। यह दिल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी नामक हृदय की मांसपेशियों की बीमारी से पीड़ित मरीज को प्रत्यारोपित किया गया। प्रत्यारोपण के बाद मरीज की हालत सामान्य है।

एयर एंबुलेंस से लखनऊ लाया गया दिल, पांच घंटे चला ऑपरेशन

निदेशक ने बताया कि दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में दिल दान में मिलने की सूचना शनिवार को मिली थी। इसके बाद देखा गया कि किस मरीज को इसे प्रत्यारोपित किया जा

सकता है। संयोग से सीतापुर निवासी मरीज इसके लिए उपयुक्त पाया गया। ऐसे में प्राइवेट एयर एंबुलेंस के माध्यम से दिल लखनऊ लाया गया। एयरपोर्ट से संस्थान की दूरी ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तय की गई। रविवार सुबह नौ बजे प्रत्यारोपण शुरू किया गया। करीब पांच घंटे चले ऑपरेशन के बाद प्रत्यारोपण पूरा हुआ।

कई विभागों का रहा योगदान

संजय गांधी पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आरके धीमन

निदेशक ने बताया कि इस प्रक्रिया ने डिंयोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी (सीवीटीएस)विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग, एनेस्थीसिया विभाग, राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल की टीमें शामिल थीं। आरएमएल अस्पताल ने दिल्ली से अंग के सुचारू स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई

प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संस्थान की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि इदय प्रत्यारोपण कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे सभी की उन्नत उपचार तक पहुंच बढ़ेगी और राज्य भर में रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण की उपलब्धि पर पूरी टीम को बधाई दी और इसे राज्य के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और अपर मुख्य सचिव अमित घोष ने कहा कि आने वाले दिनों में संस्थान प्रत्यारोपण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाएगा।

ऑपरेशन में लगी ये पूरी टीम

सीवीटीएसः प्रोफेसर एस के अग्रवाल, प्रोफेसर शांतनु पांडे, प्रोफेसर मिलिंद होते, डॉ विजय अग्रवाल, डॉ मुंशी, डॉ सिद्धार्थ, डॉ अरीब, डॉ अवनींद्र, डॉ सौरभ, डॉ विवेक, डॉ हर्ष

कार्डियोलॉजीः प्रोफेसर आदित्य कपूर, प्रोफेसर रूपाली खन्ना, प्रोफेसर सत्येन्द्र तिवारी, डॉ अंकित साहू

एनेस्थीसियाः प्रोफेसर पुनीत गोयल, डॉ अमित रस्तोगी, डॉ पल्लव सिंह, डॉ नितिन त्रिवेदी, डॉ आनंदिता कश्यप, डॉ मलिका धवल, डॉ श्रद्धा गंगेले, प्रोफेसर संजय धीरज, प्रोफेसर देवेंद्र गुप्ता

परफ्यूजनिस्टः राज कुमार यादव, संदीप कुमार

नर्सिंग स्टाफः कलावती पाल, अरविंद, श्वेता, प्रेमलता, नमन, कुलदीप

जन भवन लखनऊ में आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन, सौंपी गई स्कूल बस

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सरकारी आवास जन भवन में 1961 से संचालित परिषदीय विद्यालय को सोमवार को नया भवन मिल गया।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन भवन लखनऊ में आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया और "हमारा जन भवन" नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य और चालक को जन भवन लखनऊ स्कूल की नई बस की चाबी सौंपी गई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जनभवन, लखनऊ में 517 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधायुक्त आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन के उद्घाटन से पहले प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं विद्यालय प्रबंधन से भी भेंट की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक योजक के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन के माध्यम से एक उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत किया है। इन विद्यालयों से ही भविष्य के आर्यभट्ट, वराहमिहिर, सुश्रुत और चरक तैयार होंगे। यहीं से जगदीश चंद्र बसु और सी. वी. रमन जैसे महान वैज्ञानिक भी निकलेंगे।

अमंत्रं अक्षरं नास्ति नास्ति मूलं अनौषधं।

अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः।।

अर्थात, कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनने की क्षमता न हो, कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधि बनने की सामर्थ्य न हो। ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं जिसमें योग्यता न हो– हर व्यक्ति में योग्य बनने की क्षमता है, लेकिन उसके लिए एक सक्षम योजक आवश्यक होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद रखें, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपनी मंजिल प्राप्त करने में सफल हो सकता है।

विद्यालय अब कक्षा 10 तक उच्चीकृत

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए बताया कि जन भवन परिसर में 1961 से संचालित परिषदीय विद्यालय का कायाकल्प किया गया है। यह विद्यालय अब कक्षा 10 तक उच्चीकृत किया गया है और इसमें 14 कक्षा-कक्ष, कंप्यूटर लैब और एआई लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

नामांकन बढ़ा और ड्रॉपआउट दर कम

योगी आदित्यनाथ सरकार ने नौ वर्षों में "ऑपरेशन कायाकल्प" के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया है। इसके साथ "स्कूल चलो अभियान" के तहत बच्चों को स्कूल लाने के प्रयास किए गए हैं, जिससे नामांकन बढ़ा है और ड्रॉपआउट दर कम हुई है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को भी कक्षा 8 से 12 तक उच्चीकृत किया जा रहा है, जिससे 746 बालिका विद्यालयों को लाभ होगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर ब्लॉक में बालिकाओं के लिए 12वीं तक की शिक्षा वाला एक विद्यालय हो। "लर्निंग बाय डूइंग" कार्यक्रम और 2021 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। योगी सरकार बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है।

गोवा में डीआरएसः कचरा प्रबंधन को मिल रही नई दिशा

गोवा के सभी नगर निगम क्षेत्रों में जल्द ही लागू होगी 'डिपॉजिट रिफंड स्कीम'

SBM-U 2.0 के अंतर्गत सर्कुलर

इकॉनमी को मजबूती देगी 'कचरे से कमाई' की पहल

(जीएनएस)।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (SBM-U) 2.0 के अंतर्गत 'वेस्ट टू वेल्थ' का संकल्प साकार करते हुए गोवा एक अनूठे पर्यावरण हितकारी परिवर्तन का साक्षी बनने जा रहा है। राज्य सरकार की इस 'डिपॉजिट रिफंड स्कीम' के माध्यम से गोवा, भारत के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होने जा रहा है, जो ज़िम्मेदार कचरा प्रबंधन को एक वित्तीय प्रोत्साहन देने वाले मॉडल के रूप में लागू कर रहे हैं। गोवा में पणजी नगर निगम के मुताबिक इस योजना का प्रथम चरण जल्द ही पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा।

शहरी और पर्यटन अर्थव्यवस्था की चुनौतियां : भारतीय शहरों में पैकेजिंग वेस्ट, विशेष रूप से पेय पदार्थों की खपत से उत्पन्न होने वाले कूड़े में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। प्लास्टिक एवं कांच की बोतलें, एल्युमीनियम की कैन और मल्टी-लेयर पैकेजिंग जैसा अपशिष्ट अक्सर वर्तमान कचरा संग्रह प्रणालियों से बाहर रह जाता है। ये अपशिष्ट सामग्री विशेष रूप से समुद्र तटों, सड़कों, बाजारों और परिवहन केंद्रों पर अक्सर देखने को मिलती है। गोवा, एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के नाते, इस चुनौती का सामना और भी तीव्रता से कर रहा है।

योजना के तीन प्राथमिक उद्देश्य : नगर निगम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा साझा की गई रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के ईको-सिस्टम को पूरी तरह अपशिष्ट एवं प्रदूषण मुक्त बनाए रखना है। यह योजना तीन मुख्य उद्देश्यों को हासिल करना चाहती है, जिनमें पहली स्रोत पर अपशिष्ट की रिकवरी कर कचरे को मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) सेंटर्स पर पहुंचाकर मिश्रित कचरे में मिलने से पहले ही रोकना है। अक्सर दिखाई देने वाले कचरे को खत्म कर सार्वजनिक स्थलों और समुद्र तटों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को साफ बनाए रखना है। रीसाइक्लिंग में दक्षता हासिल करना है, ताकि स्वच्छ सामग्री के प्रवाह से रीसाइक्लिंग प्रक्रिया को मजबूत बनाए रखना भी अहम है।

नागरिकों पर केंद्रित रिवॉर्ड सिस्टम : इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका नागरिकों पर केंद्रित रिवॉर्ड सिस्टम है। इसके तहत, चिन्हित उत्पादों की खरीदारी के दौरान उनके बाजार मूल्य के ऊपर मामूली 'रिफंडेबल डिपॉजिट' या ग्रीन डिपॉजिट देना होगा। ग्राहक द्वारा जमा की गई यह अतिरिक्त राशि तब तक पैकेजिंग यूनिट से जुड़ी रहती है, जब तक उसे वापस नहीं किया जाता। इस्तेमाल के बाद, उपभोक्ता द्वारा खाली पैकेजिंग या बोतल आदि को विभागों द्वारा निर्धारित केंद्रों पर लौटाने पर यह राशि तुरंत उसे लौटा दी जाएगी। योजना के अंतर्गत खरीदारी के समय ग्राहकों को दफ-लिंक्ड उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे, जो लौटाए जाने पर भुगतान से पहले आसानी से स्कैन किए जा सकेंगे।

शुरूआती चरण में, इस नीति को रणनीतिक रूप से केवल कांच की बोतलों पर लागू किया जा रहा है, क्योंकि पर्यटन प्रधान राज्य होने के नाते गोवा में कांच का कचरा एक बड़ी चुनौती रहा है। आगामी चरणों में इसे मल्टी-लेयर प्लास्टिक और पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट बोतलों तक विस्तारित करने की योजना है। खरीदारी के समय जमा की जाने वाली राशि प्रति बोतल ₹2 से ₹10 तक होगी, जो कार्य करेगी।

व्यापक रिटर्न ईकोसिस्टम : इस पहल के अंतर्गत नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बहु-स्तरीय ढांचा तैयार किया है, जिसमें संग्रहण केंद्रों को शहरी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत रिटेल और कम्युनिटी पॉइंट्स को भी जोड़ा गया है, जिसमें खुदरा दुकानें और सामुदायिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। यह सेवाएं डोर-स्टेप के कॉन्सेप्ट पर भी विकसित की जा रही हैं, ताकि घरों से लेकर बड़े संस्थानों के लिए संग्रह की सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

DRS फ्रेमवर्क के तहत, हर एक बोतल या यूनिट पर एक निश्चित रिफंडेबल डिपॉजिट तय है। यह 'पर-यूनिट वैल्यू मैकेनिज्म' खास तौर पर सफाईमित्रों को कुछ सामग्रियों से काफी अधिक कमाई करने की अवसर देगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। यह योजना न केवल सड़कों और लैंडफिल से कचरे का बोझ कम करेगी, बल्कि मुख्य रूप से समुद्र तटों की स्वच्छता व सुंदरता में भी अभूतपूर्व परिवर्तन लाने का काम करेगी। यह योजना स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ-साथ 'ईज ऑफ लिविंग' और सर्कुलर इकॉनमी को भी बढ़ावा देगी।

रिटायर्ड आईपीएस की पत्नी की जमीन पर बना अवैध लॉनःलखनऊ विकास प्राधिकरण ने सील किया, 8 अप्रैल को जारी हुआ था नोटिस

लखनऊ (जीएनएस)। लखनऊ के खरगापुर इलाके में रिटायर्ड क्ष्हर अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की जमीन पर बने अवैध लॉन को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने सोमवार सुबह सील कर दिया। यह लॉन 'जश्न लॉन' के नाम से चल रहा था।

प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार, आवासीय जमीन को किराए पर देकर व्यावसायिक गतिविधि की जा रही थी। एलडीए ने इस मामले में लॉन संचालक रोहित कुरीच के नाम नोटिस जारी किया था। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित जमीन पर बिना वैध अनुमति के व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।

यह नियमों का उल्लंघन है। प्राधिकरण ने 8 अप्रैल को सीलिंग का नोटिस देकर लॉन का संचालन बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्देश का पालन नहीं किया गया। इस पर सोमवार को उसे सील कर दिया गया।

देवरिया जेल में बंद थे अमिताभ ठाकुर पढ़िए पूरा मामलाङ्क

लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने साल 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लाट खरीदा था। प्लाट आवंटन के दौरान पत्नी नूतन ठाकुर का नाम 'नूतन देवी' और पति का नाम 'अभिजात' अंकित कराया गया था, जबकि उनका वास्तविक नाम अमिताभ ठाकुर है। इस प्लाट का एलाटमेंट नूतन इंडस्ट्रीज के नाम पर हुआ था। लेकिन, 3 साल तक एक ईंट नहीं रखी गई।

सितंबर, 2002 में नूतन ठाकुर ने इस जमीन की लीज डीड शराब और कंस्ट्रक्शन कारोबारी संजय प्रताप सिंह को ट्रांसफर कर दी। 6 हजार स्क्वायर फीट का यह प्लॉट देवरिया शहर से लगे औद्योगिक क्षेत्र में है। यह इ-2 श्रेणी का है। यहां कोई उद्योग नहीं लगा है। अभी यहां पर श्रीनेत शांडिल्य कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है। यह संजय प्रताप सिंह का है। संजय देवरिया के शराब और कंस्ट्रक्शन के बड़े कारोबारियों में शामिल हैं।

देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में 26 साल पहले यही प्लॉट पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी को अलॉट हुआ था। सितंबर 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। जांच के दौरान देवरिया सदर कोतवाली में भी इस मामले में एक और केस दर्ज किया गया था।

पुलिस ने 10 दिसंबर को शाहजहांपुर में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया था। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

कौन हैं अमिताभ ठाकुर?

अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। बतौर अरढ उनकी पहली पोस्टिंग गोरखपुर में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बतौर रढ पहली पोस्टिंग पिथौरागढ़ में मिली। फिर वे यूपी के कई जिलों में तैनात रहे। अमिताभ की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर सोशल एक्टिविस्ट हैं। 23 मार्च, 2021 को गृह मंत्रालय ने अमिताभ ठाकुर को जबरन रिटायर कर दिया था।

मुलायम सिंह के खिलाफ दर्ज कराया था केस

बात 10 जुलाई, 2015 की है। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया था कि उन्हें मुलायम सिंह यादव ने फोन कर धमकाया और सुधर जाने की नसीहत दी। अमिताभ ने पूरी धमकी को रिकॉर्ड कर लिया था और बाद में वायरल कर दिया था। वायरल ऑडियो में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि पिछली बार से ज्यादा बुरी गत बनाऊंगा। सुधर जाओ। इस संबंध में अमिताभ ने 24 सितंबर, 2015 को हजरतगंज कोतवाली में मुलायम के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

बाद में मुलायम सिंह ने स्वीकार किया था कि उन्होंने ही अमिताभ को फोन किया था, लेकिन धमकाने की मंशा नहीं थी। इसी वाकये के बाद अमिताभ पर रेप का आरोप लगा और उन्हें सस्पेंड भी होना पड़ा था।

2021 में पहली बार गए अमिताभ ठाकुर जेल गए

घोसी से बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसके साथी ने 16 अक्टूबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आग लगा ली थी। बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी।

आत्महत्या से पहले फेसबुक लाइव पर दोनों ने एसएसपी अमित पाठक, सीओ अमरेश सिंह, दरोगा संजय राय, उनके बेटे विवेक राय और पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

अमिताभ ठाकुर पर आरोप था कि वे मुख्तार अंसारी के कहने पर अतुल राय को बचाने के लिए पीड़िता के खिलाफ तमाम दस्तावेज जारी कर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में यूपी सरकार ने एसआईटी बनाकर जांच कराई थी।

एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में बताया था कि बलात्कार पीड़िता ने 10 नवंबर, 2020 को एसएसपी वाराणसी को एक पत्र दिया था। जिसमें उसने अमिताभ ठाकुर पर बसपा सांसद अतुल राय से अदालत में झूठे सबूत गढ़ने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया था।

इसी कारण उसे आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस रिपोर्ट के आधार पर पहली बार अमिताभ ठाकुर पर सुसाइड करने के लिए मजबूर करने का प्रकरण दर्ज हुआ। उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तब वह 8 महीने जेल में रहे।

राजनीतिक पार्टी बनाई, योगी सरकार पर हमला जारी रखा

अमिताभ ठाकुर ने अगस्त, 2021 में नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी आजाद अधिकार सेना बनाई। वह खुद इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि पत्नी नूतन ठाकुर प्रवक्ता हैं।

अमिताभ ठाकुर ने 2022 में मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तब उन्होंने सीएम योगी पर हमला करते हुए आरोप लगाए थे कि उनके कार्यकाल में तमाम अलोकतांत्रिक, अराजक, दमनकारी